**भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास**

देश की अर्थव्यवस्था बैंकों के बिना विकसित नहीं हो सकती। आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में बैंकिंग के पहलू को देख सकते हैं। देश की बैंकिंग प्रणाली देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है।

 देश की बैंकिंग प्रणाली देश का अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास का आधार है। यह देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे प्रमुख हिस्सा है क्योंकि यह देश के वित्तीय क्षेत्र के 70% से अधिक  धनराशि के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है।

 देश में बैंकिंग प्रणाली में तीन प्राथमिक कार्य हैं:

* भुगतान प्रणाली के संचालन
* जमाकर्ता और लोगों की बचत का रक्षक
* व्यक्ति और कंपनियों को ऋण जारी करना

भारत में बैंकिंग प्रणाली को दो चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है

* पूर्व-स्वतंत्रता चरण (Pre-Independence Phase)(1786-1947)
* स्वतंत्रता चरण के बाद (Post- Independence Phase) (1947 से आज तक)

स्वतंत्रता अवधि के बाद को फिर से तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है-

* पूर्व राष्ट्रीयकरण अवधि (Pre-nationalisation Period)(1 947 से 1 969)
* राष्ट्रीयकरण अवधि(Post nationalisation Period) (1969 से 1991)
* उदारीकरण अवधि (Liberalisation Period) (1991 से आज तक)

**पूर्व-स्वतंत्रता चरण (1786-1947)**

भारत में बैंकिंग प्रणाली का उद्गम 1786 में **बैंक ऑफ कलकत्ता** की स्थापना के साथ हुआ ।

* + 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के तहत प्रेसीडेंसी बैंकों, **बैंक ऑफ बंगाल**, **बैंक ऑफ बॉम्बे** और **बैंक ऑफ मद्रास** की स्थापना की गयी I
  + 1935 में, प्रेसीडेंसीबैंकों का विलय कर दिया गया और **इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया** नामक एक नया बैंक बनाया गया ।
  + इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में **भारतीय स्टेट बैंक** बना।
  + 1865 में इलाहाबाद में पहली भारतीय स्वामित्व वाली **इलाहाबाद बैंक** की स्थापना हुई थी।
  + 1895 में, **पंजाब नेशनल बैंक** स्थापित किया गया था।
  + **बैंक ऑफ इंडिया** की स्थापना **1906** में मुंबई में हुई थी।
  + 1906 और 1913 के बीच **केनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ मैसूर** वाणिज्यिक बैंक स्थापित किए गए ।
  + भारतीय केंद्रीय बैंक, आरबीआई **हिल्टन-यंग आयोग** की सिफारिश पर **1935** में स्थापित किया गया था।

उस समय, बैंकिंग प्रणाली केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित रहा तथा ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की जरूरत पूरी तरह से उपेक्षित थी।

**स्वतंत्रता चरण के बाद (1947 से अब तक )**

* + स्वतंत्रता के समय, संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र निजी स्वामित्व में था। देश की ग्रामीण आबादी को अपनी आवश्यकताओं के लिए छोटे  उधारदाताओं पर निर्भर होना पड़ता था । इन मुद्दों को हल करने और अर्थव्यवस्था का बेहतर विकास करने के लिए भारत सरकार ने **1949 में भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण** कर दिया ।
  + **1955** में **इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ** उसे **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** का नाम दिया गया।
  + 1949 में **बैंकिंग विनियमन अधिनियम** (Banking Regulation Act,1949) लागू किया गया ।

**राष्ट्रीयकरण अवधि (1969 से 1991)**

* + 1969 में, भारत सरकार ने **14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण** किया जिनके जमा-पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी । नीचे बैंको की सूची प्रस्तुत है-

1. इलाहाबाद बैंक
2. बैंक ऑफ इंडिया
3. पंजाब नेशनल बैंक
4. बैंक ऑफ बड़ौदा
5. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
6. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
7. कैनरा बैंक
8. देना बैंक
9. इंडियन ओवरसीज बैंक
10. इंडियन बैंक
11. संयुक्त बैंक
12. सिंडिकेट बैंक
13. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
14. यूको बैंक

राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली बेहद विकसित हुई लेकिन समाज के ग्रामीण, कमजोर वर्ग और कृषि को अभी भी सिस्टम के तहत कवर नहीं किया गया था।

इन मुद्दों को हल करने के लिए, 1974 में **नरसिंहम समिति** ने **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)** की स्थापना की सिफारिश की थी। **2 अक्टूबर 1975** को, आरआरबी को ग्रामीण और कृषि विकास के लिए ऋण की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

* + वर्ष **1980** में **छह** और बैंकों को और अधिक राष्ट्रीयकृत किया गया। राष्ट्रीयकरण की दूसरी लहर के साथ, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने का लक्ष्य भी 40% तक बढ़ाया गया।

1. आंध्र बैंक
2. निगम बैंक
3. नई बैंक ऑफ इंडिया
4. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
5. पंजाब एंड सिंध बैंक
6. विजया बैंक

**उदारीकरण चरण (1990 से अब तक )**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए, भारत सरकार ने **श्री एम नरसिंहम** की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की। एम नरसिमहम समिति ने देश में बैंकिंग प्रणाली को सुधारने के लिए कई सिफारिश की। जिनमे से कुछ प्रमुख है-

* सिफारिशों का प्रमुख जोर बैंकों को प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनाने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए अनुकूल बनाना था।
* समिति ने बैंकों के और अधिक राष्ट्रीयकरण न करने का सुझाव दिया।
* विदेशी बैंकों को भारत में या तो शाखाओं या सहायक कंपनियों के रूप में कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी।
* बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, समिति ने सुझाव दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए।
* इस बात पर बल दिया गया  कि बैंकों को बैंकिंग के रूढ़िवादी और पारंपरिक प्रणाली को छोड़ने और मर्चेंट बैंकिंग और अंडरराइटिंग, रिटेल बैंकिंग जैसे प्रगतिशील कार्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
* अब, विदेशी बैंकों और भारतीय बैंकों ने इन और अन्य नए प्रकार के वित्तीय सेवाओं में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।
* 10 प्राइवेट बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आरबीआई से  लाइसेंस मिला। ये **ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी एस बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, इंडसइंड बैंक, सेंच्युरियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, टाइम्स बैंक और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक** थे I

भारत सरकार ने समिति की सभी प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

**भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आधुनिक विकास:**

* + **कोटक महिंद्रा बैंक** और **यस बैंक** को वर्ष **2003** और **2004** में सिस्टम में प्रवेश के लिए आरबीआई से लाइसेंस मिला।
  + 2014 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने **आईडीएफसी** और **बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज** को सैद्धांतिक रूप से बैंकों की स्थापना के लिए अनुमोदित किया ।

आज, भारतीय बैंकिंग उद्योग सबसे अधिक विकासशील उत्कृष्ठ उद्योगों में से एक है। किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली को प्रभावी होना चाहिए क्योंकि यह देश के आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाता है।

**History of Banking in India in Brief (Before & After Independence) : Bank & Insurance**

Today, our banking system is mainly divided into commercial banks (Both Public and Private Banks), Regional Rural Banks, Cooperative Banks etc. The important phase in the history of Indian banking was nationalization of banks that makes way for the Indian Economy to enter in the top 10 economies of the world. In this article, we will brief you about the history of banking in India.

**History of Banking in India in Brief**

**(Before & After Independence)**

**Phases of Indian Banking System**

The advancement in the Indian banking system is classified into **3 distinct phases**:

1. The Pre-Independence Phase i.e. before 1947

2. Second Phase from 1947 to 1991

3. Third Phase 1991 and beyond

**1. The Pre-Independence Phase i.e. before 1947**

* This phase is characterized by the presence of a large number of banks (**more than 600**).
* Banking system commenced in India with the foundation of **Bank of Hindustan** in Calcutta (now Kolkata) in **1770** which ceased **to operate in 1832.**
* After that many banks came but were not successful like:  
  (1) General Bank of India (1786-1791)  
  (2) Oudh Commercial Bank (1881-1958) – the **first commercial bank of India.**
* Whereas some are successful and continue to lead even now like:  
  **(1) Allahabad Bank** (est. 1865)  
  **(2) Punjab National Bank** (est. 1894, with HQ in Lahore (that time))  
  **(3) Bank of India** (est. 1906)  
  **(4) Bank of Baroda** (est. 1908)  
  **(5) Central Bank of India** (est. 1911)
* While some others like **Bank of Bengal** (est. 1806), **Bank of Bombay** (est. 1840), **Bank of Madras**(est. 1843) merged into a single entity in **1921** which came to be known as **Imperial Bank of India**.
* **Imperial Bank of India was later renamed in 1955 as the State Bank of India**.
* **In April 1935,** **Reserve Bank of India** was formed based on the recommendation of **Hilton Young Commission (set up in 1926).**
* In this time period, most of the **bank were small in size and suffered from a high rate of failures**. As a result, public confidence is low in these banks and deposit mobilization was also very slow. People continued to rely on the unorganized sector (moneylenders and indigenous bankers).

**2. The second phase from 1947 to 1991**

* Broadly the main characteristic feature of this phase is the **Nationalization of the bank**.
* With the view of economic planning, nationalization emerged as an effective measure.   
  **Need for nationalization in India:**   
  (a) The banks mostly catered to the needs of large industries, big business houses.  
  (b) Sectors such as agriculture, small-scale industries and exports were lagging behind.  
  (c) The poor masses continued to be exploited by the moneylenders.
* Following this, in the year **1949, 1st January** the **Reserve Bank of India was nationalized.**
* **Fourteen commercial banks** were nationalized on**19th July 1969.** Smt. Indira Gandhi was the Prime Minister of India, during in 1969. The following banks are nationalized:  
  **1**. Central Bank of India             
  **2.** Bank of India          **3.** Punjab National Bank  
  **4.** Bank of Baroda                     
  **5.**United Commercial Bank             
  **6**. Canara Bank         **7.** Dena Bank                           
  **8.** United Bank                    **9.** Syndicate Bank             **10.** Allahabad Bank             **11.**Indian Bank                             
  **12.** Union Bank of India  
  **13.** Bank of Maharashtra           
  **14.** Indian Overseas Bank
* **Six more commercial banks were nationalized in April 1980**. These are mentioned below:  
  **1.** Andhra Bank         **2.** Corporation Bank                     **3.** New Bank of India  
  **4.** Oriental Bank of Commerce                         **5.** Punjab & Sindh Bank               **6**.Vijaya Bank.
* Meanwhile, on the recommendation of **the Narasimham committee**, Regional Rural Banks (RRBs) were formed on **Oct 2, 1975**. The objective behind the formation of RRBs was **to serve the large unserved population of rural areas and promoting financial inclusion.**
* With a view to meet the specific requirement from the different sector (i.e. agriculture, housing, foreign trade, industry) some apex level banking institutions were also set up like:(a) **NABARD** (est. 1982)  
  (b) **EXIM** (est. 1982)  
  (c) **NHB** (est. 1988)  
  (d) **SIDBI** (est. 1990)

**Impact of Nationalization:**

* Improved efficiency in the Banking system – since the public‘s confidence got boosted.
* Sectors such as Agriculture, small and medium industries started getting funds which led to economic growth.
* Increased penetration of Bank branches in rural areas.

**3. Third phase 1991 and beyond**

* This period saw remarkable growth in the process of development of banks with the liberalization of economic policies**.**
* Even after nationalization and the subsequent regulations that followed, a large portion of masses is untouched by the banking services.
* Considering this, in 1991, **the Narasimham committee** gave its recommendation i.e. to allow the entry of private sector players into the banking system.
* Following this, RBI gave license to 10 private entities, out of which few survived the market demands, which are- **ICICI, HDFC, Axis Bank, IndusInd Bank, DCB**.
* In **1998, the Narsimham committee** again recommended the entry of more private players. As a result, RBI gave a license to the following newbies:  
  **(a) Kotak Mahindra Bank (2001)  
  (b)Yes Bank (2004)**
* In **2013-14**, the third round of bank licensing took place and in 2015, **IDFC bank and Bandhan Bank emerged.**
* In order to further financial inclusion, RBI also proposed to set up 2 new kinds of banks i.e. **Payment Banks and Small Banks.**
* In 2015, RBI gave in-principle licence to **11 entities** to launch **Payments Bank** and granted 'in-principle' approval to the **10 applicants to set up Small Finance Banks.**

**Note:**

* The RBI issued a license to the bank under **Section 22(1) of the Banking Regulation Act, 1949**, to carry on the business of **Small finance bank (SFB) and Payments Bank in India.**

**Committee on Small Banks -**The applications were analyzed and evaluated by an External Advisory Committee (EAC). The EAC for small banks was chaired by **Usha Thorat**, former deputy governor, RBI.

**Committee on Payment Banks -**These applications were analyzed and evaluated by an External Advisory Committee (EAC). The EAC Committee for Payment Banks was chaired by**Dr Nachiket Mor,** Director, Central Board of the Reserve Bank of India.

**Nationalisation of Banks in India**

Nationalization refers to the transfer of public sector assets to be operated or owned by the state or central government. In India, the banks which were previously functioning under private sector were transferred to the public sector by the act of nationalization and thus the nationalized banks came into existence.

After independence the Government of India (GOI) adopted planned economic development for the country (India). Accordingly, five year plans came into existence since 1951. This economic planning basically aimed at social ownership of the means of production. However, commercial banks were in the private sector those days. In 1950-51 there were 430 commercial banks. The Government of India had some social objectives of planning. These commercial banks failed helping the government in attaining these objectives.

Thus, one of the most crucial evolutions that led to the foundation of current Banking system in India was the Nationalization of Banks.

The Supreme Court in the case of **All India Bank Officers’ Confederation v. Union of India,** (1989) 4 SCC 90,remarked that the object of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act was to nationalize the banks to render the largest good to the largest number of people. The object of Section 9 of the Act which is regarding Central Government’s power to make a scheme for constitution of Board of Directors, is to give the Board a truly representative character so as to reflect the genuine interests of the various persons manning or dealing with the bank as an industry and a commercial enterprise.

**Brief History of nationalisation of Banks in India**

In India, Nationalization of banks was done in 2 phases. The initial phase of nationalization commenced in the year 1955 when the former Imperial Bank of India became the State Bank of India with the Act of parliament. During the year 1959, 7 subsidiaries were nationalized & connected with SBI one by one. This heralded a new beginning in the banking system of India. Even before this RBI had been nationalized on Jan 1, 1949.

The second phase of nationalization started in the year 1969 with the nationalization of 14 main commercial banks in India. In the year 1980, six more commercial banks were nationalized & became public sector banks. Subsequently, the Public Sector Undertaking banks prolonged their reach & grew in leaps & bounds. In India, the nationalized banks expanded their branches & stretched their activities across the nation. The Public Sector banks launched new programs and schemes to cater all sections of the society. Therefore, nationalization of Banks in India helped the masses to avail banking services at reasonable cost.

**Chronology of Nationalization of Banks**

• 1949 – RBI nationalized.

• 1955 – SBI nationalized.

• 1959 – Seven subsidiaries nationalized & associated with State Bank of India

1. State Bank of Bikaner and Jaipur   
2. State Bank of Hyderabad   
3. State Bank of Indore   
4. State Bank of Mysore   
5. State Bank of Patiala   
6. State Bank of Saurashtra   
7. State Bank of Travancore

• 1969 – All commercial banks with a deposit base over Rs.50 crores were nationalized. It was considered that banks were controlled by business houses and thus failed in catering to the credit needs of poor sections such as cottage industry, village industry, farmers, craft men, etc. Fourteen major commercial Banks nationalized on July 19th, 1969.

1. Allahabad Bank   
2. Bank of Baroda   
3. Bank of India   
4. Bank of Maharashtra   
5. Canara Bank   
6. Central Bank of India   
7. Dena Bank   
8. Indian Bank   
9. Indian Overseas Bank   
10. Punjab National Bank   
11. Syndicate Bank   
12. UCO Bank   
13. Union Bank of India   
14. United Bank of India

• 1980 – Six more commercial Banks nationalized with deposits over 200 crores.

1. Andhra Bank   
2. Corporation Bank   
3. New Bank of India   
4. Oriental Bank of Commerce   
5. Punjab & Sindh Bank   
6. Vijaya Bank

Later on, in the year 1993, the government merged New Bank of India with Punjab National Bank.

**Objectives Behind Nationalisation of Banks in India**

The nationalisation of commercial banks took place with an aim to achieve following major objectives.

1. **Social Welfare** : It was the need of the hour to direct the funds for the needy and required sectors of the indian economy. Sector such as agriculture, small and village industries were in need of funds for their expansion and further economic development.
2. **Controlling Private Monopolies** : Prior to nationalisation many banks were controlled by private business houses and corporate families. It was necessary to check these monopolies in order to ensure a smooth supply of credit to socially desirable sections.
3. **Expansion of Banking** : In a large country like India the numbers of banks existing those days were certainly inadequate. It was necessary to spread banking across the country. It could be done through expanding banking network (by opening new bank branches) in the un-banked areas.
4. **Reducing Regional Imbalance** : In a country like India where we have a urban-rural divide; it was necessary for banks to go in the rural areas where the banking facilities were not available. In order to reduce this regional imbalance nationalisation was justified:
5. **Priority Sector Lending** : In India, the agriculture sector and its allied activities were the largest contributor to the national income. Thus these were labeled as the priority sectors. But unfortunately they were deprived of their due share in the credit. Nationalisation was urgently needed for catering funds to them.
6. **Developing Banking Habits** : In India more than 70% population used to stay in rural areas. It was necessary to develop the banking habit among such a large population.

**Demerits, Limitations - Bank Nationalisation in India**

Though the nationalisation of commercial banks was undertaken with tall objectives, in many senses it failed in attaining them. In fact it converted many of the banking institutions in the loss making entities. The reasons were obvious lethargic working, lack of accountability, lack of profit motive, political interference, etc. Under this backdrop it is necessary to have a critical look to the whole process of nationalisation in the period after bank nationalisation.

The major limitations of the bank nationalisation in India are:-

1. **Inadequate banking facilities** : Even though banks have spread across the country; still many parts of the country are unbanked. Especially in the backward states such as the Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and north-eastern states of India.
2. **Limited resources mobilized and allocated** : The resources mobilized after the nationalisation is not sufficient if we consider the needs of the Indian economy. Some times the deposits mobilized are enough but the resource allocation is not as per the expansions.
3. **Lowered efficiency and profits** : After nationalisation banks went in the government sector. Many times political forces pressurized them. Banking was not done on a professional and ethical grounds. It resulted into lower efficiency and poor profitability of banks.
4. **Increased expenditure** : Due to huge expansion in a branch network, large staff administrative expenditure, trade union struggle, etc. banks expenditure increased to a dangerous levels.
5. **Political and Administrative Interference** : Many public sector banks badly suffered due to the political interference. It was seen in arranging loan meals. It ultimately resulted in huge non-performing assets (NPA) of these banks and inefficiency.

These are several limitations faced by the banks nationalisation in India.

Apart from this there are certain other limitations as well, such as weak infrastructure, poor competitiveness, etc.

**बैंकों का राष्ट्रीयकरण**

इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्वकाल में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अहम फ़ैसला किया था.   
  
उन्होंने 19 जुलाई, 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था. इन बैंकों पर अधिकतर बड़े औद्योगिक घरानों का कब्ज़ा था.   
  
इसके बाद राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर 1980 में हुआ जिसके तहत सात और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया. अब भारत में 27 बैंक राष्ट्रीयकृत हैं.   
  
इसके पहले तक केवल एक बैंक- भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्रीयकृत था.   
  
इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में कर दिया गया था और 1958 में इसके सहयोगी बैंकों को भी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया.   
  
विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीयकरण के बाद भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है.   
  
हालांकि भारत में अब विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंक सक्रिय हैं. लेकिन एक अनुमान के अनुसार बैंकों की सेवाएँ लेनेवाले लगभग 90 फ़ीसदी लोग अब भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ही सेवाएँ लेते हैं.

### ****इतिहास****

बैंकिंग का इतिहास सभ्यताओं के विकास के साथ ही माना जा सकता है। भारत एवं विश्व में श्रेणी और निगमों के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था का संचालन किया जाता था। अतीत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि कई वर्ग एवं समुदाय इन्हीं माध्यमों से व्यापार एवं अन्य ज़रूरतों के लिये धन प्राप्त करते थे। इतना ही नहीं ये संस्थान लोगों का धन जमा भी कराते थे जिस पर ब्याज देय होता था। भारत में यूरोपियों विशेषकर अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात् बैंकिंग क्षेत्र में कुछ तेज़ी देखने को मिलती है। हालाँकि ये संस्थान पूर्णतः ब्रिटिश हितों एवं ब्रिटिश कंपनियों के लिये ही सेवाएँ दे रहे थे, यही स्थिति बाद में भारतीय बैंकिंग संस्थानों में भी देखी जा सकती थी। स्वतंत्रता के पश्चात् भी बैंकों की मानसिकता एवं कार्यपद्धति में कोई बदलाव नहीं देखा गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व भारत की 80 प्रतिशत पूंजी निजी बैंकों के पास ही थी, साथ ही इन संस्थानों का भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में कोई योगदान नहीं था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य समस्याएँ भी थीं।

### ****बैंकों का राष्ट्रीयकरण- कारक****

भारत का बैंकिंग क्षेत्र स्वतंत्रता के पश्चात् प्रमुख रूप से निजी हाथों में था। एक ओर जहाँ भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहयोग की इन बैंकों की कोई रुचि नहीं थी, वहीं दूसरी ओर इनका प्रशासन एवं विनियमन भी खराब स्थिति में था। वर्ष 1947-1955 के बीच लगभग छोटे-बड़े 300 से भी अधिक बैंक बंद हो चुके थे, साथ ही इन बैंकों में जमा लोगों की जमा पूंजी भी डूब चुकी थी। ये बैंक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की पहुँच से दूर थे तथा इन बैंकों के माध्यम से कुछ उद्योग कालाबाज़ारी तथा जमाखोरी में भी लिप्त थे।

उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त तत्कालीन समय में सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये विभिन्न प्रयास कर रही थी, भारत में समावेश को बढ़ावा देने के लिये तथा लोगों विशेषकर ग्रामीण आबादी को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिये सरकार बैंकों का समर्थन चाहती थी किंतु बैंकों पर सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के बगैर यह मुमकिन नहीं था। अतः सरकार द्वारा वर्ष 1969 में और बाद में वर्ष 1980 में बैंकों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया।

### ****बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं विलय****

विश्व में 1950 के दशक से पूर्व बैंकिंग क्षेत्र मुख्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हो रहा था। द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल देशों को गंभीर आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी जिससे इन देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा था। इससे उबरने के लिये विभिन्न देशों विशेषकर यूरोपीय देशों द्वारा कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिससे कि इन देशों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी तथा गरीबी, ग्रामीण-शहरी अंतराल भी अत्यधिक था। सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र में अधिक सुधार नहीं हो पा रहा था। भारत सरकार के समक्ष पूंजी की भी बड़ी समस्या थी क्योंकि संसाधन सीमित थे। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1969 में सरकार ने 14 बैंकों (जिनकी पूँजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी) का राष्ट्रीयकरण किया। २०० करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि वाले और छ: बैंकों का राष्ट्रीयकरण बाद में 1980 में किया गया। सरकार ने समय-समय पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ इन्हीं उद्देश्यों के चलते कुछ बैंकों का विलय भी किया है। बैंकों की स्थिति सुधारने के लिये बैंकों के विलय की सिफारिश पहले ही नरसिंहम समिति तथा पी.जे. नायक समिति द्वारा की जाती रही है। भारतीय बैंकिंग संघ के अनुसार, वर्ष 1986 से अब तक लगभग 50 बैंकों का विलय किया गया है। न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय अतीत का पहला बड़ा विलय माना जाता है। कुछ समय पश्चात् वर्ष 2017 में भारतीय महिला बैंक एवं पाँच अन्य बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में विलय किया गया था। इस विलय के पश्चात् SBI विश्व के 50 बढ़े बैंकों की सूची में शामिल हो गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में विजया बैंक एवं देना बैंक का बैंक ऑफ़ बड़ौदा में भी विलय किया गया।

**राष्ट्रीयकरण के पीछे आर्थिक तर्क**

* महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए ऋण की पहुंच और प्रवाह से संबंधित मुद्दे।
* बैंक कृषि और उद्योग को पर्याप्त ऋण नहीं दे रहे थे।
* बैंकों को व्यापार के लिए ऋण देने में अधिक रुचि थी।
* बैंकों के पतन से लोगों में संकट पैदा हो रहा था।
* बैंकिंग क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन।
* लोगों की बैंकिंग आदतों का विकास करना।

वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के मूल उद्देश्य

(अ) बैंकिंग सुविधाओं तथा सेवाओं का विस्तार करना, राष्ट्रीयकरण के पहले बैंकिग सेवाए कुछ पूजीपतियों एवं बड़े व्यापारी तथा किसानों तक ही सीमित थीं जिसके फलस्वरूप समाज के दो वर्गों में बहुत बड़ी आर्थिक दरार उत्पन्न हो गई थी। इस आर्थिक विषमता को दूर करने हेतु बैंकिग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ समाज में सभी वर्गों विशेषत: ग्रामीण कस्बाई क्षेत्रों में बसे कमजोर वर्गों तक पहुंचाने का मूल उद्देश्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण में निहित है।

(आ) देश का आर्थिक विकास दूसरा उद्देश्य माना जा सकता है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि बैंक राष्ट्रीयकरण के पहले देश में आर्थिक संकट उत्पन्न होने के कारण आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध हो गई थी। अत: देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए बैंको का राष्ट्रीयकरण किया जाना बहुत ही आवश्यक हो गया था क्योंकि किसी भी देश की प्रगति एवं खुशहाली के लिए उसके आर्थिक विकास की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

(इ) बैंक राष्ट्रीयकरण का तीसरा उद्देश्य था देश में बेरोजगारी की समस्या। यह भारतवर्ष की मुख्य चिंता रही है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोजा जा सकता था क्योंकि शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता के माध्यम से उनके अपने निजी उद्योग या स्वरोजगार के अनेक साधनों में वृद्धि करके बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता था। जब तक देश में बेरोजगारी की समस्या का उचित हल नहीं होता तब तक उसके विकास कार्य में तेजी नहीं आ सकती। इस तथ्य को दृष्टिगत रखकर बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाना जरूरी हो गया था ताकि बैंकिंग सेवाओं तथा सहायता का लाभ शिक्षित बेरोजगारों को मिलकर वे अपनी उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त कर सकें।

(ई) बैंक राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य यह भी था कि समाज के कम जोर वर्गों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लोगों का बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं के माध्यम से उत्थान करके देश की आर्थिक उन्नति को एक नई दिशा प्रदान कराना। देश के कमजोर वर्ग तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लोग अर्थात् छोटे तथा मंझोले किसान, भूमिहीन मजदूर, शिक्षित बेरोजगार, छोटे कारीगर आदि की आर्थिक उन्नति में योगदान दिया जाना बहुत आवश्यक हो गया था क्योंकि ऐसे वर्गों के लोग देशभर में फैले हुए थे और उनकी संख्या काफी थी। समाज में वे अपेक्षित भी थे। अत: वर्गों के लोगों में नया आत्मविश्वास पैदा करके उन्हें उन्नति एवं खुशाहाली के मार्ग पर लाना देश की सर्वागीण प्रगति के लिए बहुत जरुरी हो गया था। अत: बैंकिंग सुविधा के माध्यम से ही इनका विकास संभव था। फलत: बैंक राष्ट्रीयकरण का विचार सामने आया।

(उ) बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक और मूल उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार तथा कृषि एवं लघु उद्योगों के क्षेत्रों की समुचित प्रगति किया जाना। भारतीय किसान युग-युग से उपेक्षित ही रहा और हर बार वह औरों से चुसता ही गया। फलत: वह गरीबी की पर्तों से ऊपर नहीं उठ सका था। यही हालत कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की थी। ये व्यवसाय अधिकतर कृषि पर ही निर्भर करते थे और कृषि और कृषि का क्षेत्र उपेक्षित तथा अविकसित होने के कारण इन उद्योगों का भी प्रगति नहीं हो पाई थी। इस प्रकार, कृषि एवं लघु उद्योग जैसे उपेक्षित क्षेत्रों की ओर उचित ध्यान देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाना राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक तथा अनिवार्य हो गया था।

(ऊ) देश के बीमार उद्योगों को पुनरूज्जीवित करके नए लघु-स्तरीय उद्योगों के नव निर्माण को बढ़ावा देना भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य था। बीमार उद्योगों के कारण बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होकर आर्थिक मंदी फैलने का यह भी एक कारण था अत: ऐसे उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर पुनरूज्जीवित करना आवश्यक था। इसके साथ ही लघु-स्तरीय उद्योगों की संख्या पर्याप्त नहीं थी जिससे कस्बाई क्षेत्रों की प्रगति में तेजी नहीं आ पा रही थी और ऐसे उद्यमी हमेशा विदेश की ओर आंखें लगाकर बैठे हुए होते थे। अत: देश की प्रगति के लिए लघु-स्तरीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना भी अत्यंत जरूरी था जोकि आर्थिक सहायता के बगैर असंभव-सा प्रतीत होता था। अत: बैंकों द्वारा आर्थिक नियोजन के लिए उनपर सरकार का स्वामित्य होना एक आवश्यक बात हो गई थी। इस प्रकार अनेक सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के कारण बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिससे कि कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों की उन्नति के साथ समाज की और प्रकारांतर से राष्ट्र की प्रगति हो।

### ****राष्ट्रीयकरण के परिणाम****

### 1. शाखा विस्तार (Branch Expansion):

### राष्ट्रीयकरण के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि शाखाओं के विस्तार में हुई । अग्रणी बैंक योजना (Lead Bank Scheme) एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks) स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ |

### राष्ट्रीयकरण के बाद 45 वर्षों में बैंक शाखाओं की संख्या में लगभग 35 गुना वृद्धि हुई है । ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाएँ इस अवधि में 1860 से बढकर 39439 हो गई है । सन् 1969 में 63800 जनसंख्या के लिये एक बैंक शाखा थी जो वर्ष 2013 में 12000 जनसंख्या के लिए एक बैंक शाखा में परिवर्तित हो गई है ।

### वर्तमान में एक बैंक शाखा 16 किलोमीटर के घेरे के अंदर के ग्रामों में सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं । कुछ बैंकों ने चलती-फिरती शाखाएँ (Mobile Branch) भी स्थापित की हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है और इससे ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के साथ ही कृषि क्षेत्र को संस्थागत साख प्राप्त होने लगी है ।

### 2. प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण सुविधाएँ (Credit Facilities to Priority Sectors):

### राष्ट्रीयकरण से पूर्व तक व्यापारिक बैंकों ने कृषकों, छोटे उद्योगपतियों, कारीगरों एवं निर्यात में की उपेक्षा की थी । राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । सन् 1969 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को कुल ऋणों का केवल 15 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ था जो बढकर सन् 2007 में लगभग 54 प्रतिशत हो गया ।

### उधार दी गई राशि का विश्लेषण करने से यह तथ्य सामने आता है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र को सन् 1969 में 440 करोड़ रुपये के ऋण दिये थे जो बढकर सन् 2007 में 1,46,550 करोड़ रुपये हो गये । इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीयकरण के बाद प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है ।

### 3. जमाओं को गतिशील करना (Deposit Mobilization):

### राष्ट्रीयकरण के बाद यद्यपि बैंक जमाओं में वृद्धि हुई है, तथापि वृद्धि की दर धीमी रही है । जमाओं में वृद्धि की दर इस अवधि में लगभग 17 प्रतिशत रही । जमा राशि में वृद्धि का श्रेय मुख्यतः शाखाओं में विस्तार को है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विदेशी बैंकों में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा राशि में कहीं अधिक वृद्धि हुई है ।

### 4. साख में विस्तार (Credit Expansion):

### राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने साख का विस्तार बहुत तेजी से किया । सामान्यतः बैंक साख का विस्तार बैंक जमा के विस्तार के साथ-साथ होता है, किन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक साख का विस्तार लगभग 24 प्रतिशत की दर से हुआ जबकि बैंक जमा में केवल 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

### 5. विकास वित्त का विस्तार (Expansion of Development Finance):

### राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने अपने पारम्परिक उद्देश्य (अर्थात् हिस्सेदारों को लाभ पहुँचाना) के कार्य का परित्याग कर दिया है और अब वे विकास वित्त में महत्वपूर्ण योगदान देने लगे है । अल्पकालीन ऋणों की अपेक्षा अब व्यापारिक बैंक विकास-और विस्तार की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए मध्यम और दीर्घकालीन ऋणों की अपनी क्रियाओं को बढा रहे हैं । अग्रणी बैंक योजना (Lead Bank Scheme) भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

### 6. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme):

### यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में असन्तुलन को दूर करने एवं ग्रामीण जनता के सर्वागीण विकास का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है । वर्ष 1999-2000 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 19,240 करोड़ रुपये के ऋण समाज के कमजोर वर्गों को दिए । यह राशि कुल दिए गए ऋणों का 7.2 प्रतिशत थी ।

### 7. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश वृद्धि (Increase in Investment in Government Securities):

### राष्ट्रीयकरण से पूर्व व्यापारिक बैंकों द्वारा अपने कूल निक्षेपों का 20 से 25 प्रतिशत भाग सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाता था । अब यह प्रतिशत 40 से 45 प्रतिशत हो गया है । इससे सरकार को अल्पकालीन वित्तीय सुविधाएँ सरलता से प्राप्त होने लगी हैं ।

### उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंकों की शाखाओं की संख्या में हुई तीव्र वृद्धि से देश के कोने-कोने में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ है । इस विधि में बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली साख की दिशा में भी परिवर्तन हुआ है ।

### राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि, छोटे उद्योग, ग्रामीण दस्तकार, फुटकर व्यवसायी आदि को भी प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्राप्त होने लगे है । गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों में भी व्यापारिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है ।

### राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क (Arguments against Bank Nationalization):

### बैंकों के राष्ट्रीयकरण का देश में विरोध भी हुआ । आलोचकों का कहना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण आर्थिक विचारधारा से प्रभावित न होकर राजनैतिक विचारधारा से प्रभावित है । इसका प्रमाण यह है कि अभी-अभी बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण लगा था । इसके परिणाम आने के पूर्व ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक चौकने वाली घटना है ।

### (1) आलोचकों का कहना है कि भारत में अब तक किया गया राष्ट्रीयकरण असफल रहा है । बैंक भी अब राष्ट्रीयकृत व्यवसाय की श्रेणी में आ गये हैं । अन्य उद्योगों तथा व्यवसाय की तरह बैंकों के राष्ट्रीयकरण भी असफल होगा ।

### (2) बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश के औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों को काफी नुकसान होगा ।

### (3) बैंकों का राष्ट्रीयकरण कांग्रेस की आपसी फूट का परिणाम है । यह आर्थिक कारणों की अपेक्षा राजनीतिक कारणों से किया गया है ।

### (4) राष्ट्रीयकरण के बाद गरीब लोगों को, कृषकों से तथा लघु उद्योगपतियों को इससे विशेष लाभ नहीं होगा । सरकारी कर्मचारी सारी व्यवस्था को खराब करके रख देंगे ।

### (5) राष्ट्रीयकृत उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था कुशल नहीं होगी ।

### ****राष्ट्रीकृत बैंक एवं निजी क्षेत्र के बैंक****

उदारीकरण के पश्चात् निजी क्षेत्र को भी बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। वर्ष 1994 में इस तरह का पहला बैंक आईसीआईसीआई बैंक था जिसे उदारीकरण के पश्चात् बैंक के लिये लाइसेंस दिया गया था। वर्तमान में निजी क्षेत्र के कई बैंक कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र को बैंकिंग में शामिल करने से इस क्षेत्र में तेज़ी आई तथा लोगों के लिये बैंकिंग सेवाएँ सर्वसुलभ हो गईं। इन बैंकों ने नए-नए उत्पादों को बाज़ार में उतारा एवं धीरे-धीरे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्द्धा करने लगे। ये बैंक पूर्णतः बैंकिंग मूल्यों पर आधारित हैं एवं सिर्फ अपने ग्राहकों के प्रति ही जिम्मेदार हैं। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) अर्थात् राष्ट्रीकृत बैंकों को अपनी उत्तरजीविता के साथ-साथ जनता के प्रति सामाजिक-आर्थिक दायित्व का भी निर्वहन करना पड़ रहा है। इससे PSB के लिये निजी बैंकों से प्रतिस्पर्द्धा करना मुश्किल हो रहा है। विभिन्न राष्ट्रीकृत बैंक गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) की अधिकता तथा खराब कार्यकरण के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य समस्या इन बैंकों पर नियंत्रण को लेकर भी है, सरकार तथा RBI, दोनों के द्वारा बैंकों को दिशा निर्देश दिये जाते हैं इससे असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है।

यदि आधारभूत संकेतकों पर ध्यान दें तो इंगित होता है कि PSB की स्थिति में गिरावट आई है। मार्च 2019 के अंत में सकल NPA अनुपात 11.2 प्रतिशत था तथा PSB बैंकों की परिसंपत्ति पर प्रतिफल (Return of Assets) वित्तीय वर्ष 2018 के लिये 0.8 प्रतिशत था, जबकि इक्विटी पर प्रतिफल (Return of Equity) की दर नकारात्मक थी। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष नवीन बैंक शाखाएँ खोलने की दर में भी 25 प्रतिशत की गिरावट आई है।

### ****सार्वजनिक बैंक: अभी भी मज़बूत****

उपर्युक्त स्थिति के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अभी भी मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। बाज़ार की कुल बैंक उधारी (Credits) एवं कुल जमा (Deposits) अभी भी क्रमशः 63.2 प्रतिशत एवं 66.9 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ही मौजूद है। हालाँकि NPA बैंकों के लिये बड़ी समस्या बनकर उभरा है। किंतु इसमें भी सुधार देखा जा रहा है, साथ ही सरकार, RBI एवं संबंधित बैंक अपने फँसे हुए ऋण की वसूली के लिये प्रयास कर रहे हैं।

कुछ विशेषज्ञ बैंकों की कमज़ोर हो रही स्थिति को देखते हुए इनके निजीकरण का विचार प्रस्तुत करते रहे हैं। भारत जैसे देश में जहाँ गंभीर आर्थिक असमानताएँ मौजूद हैं तथा लोगों की स्थिति में सुधार के लिये बैंकिंग व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे में निजीकरण का विचार किसी भी रूप में उचित नहीं समझा जा सकता है। निजीकरण के स्थान पर सरकार को बैंकों की स्थिति में सुधार के लिये आगे आना होगा, साथ ही बैंकों के गवर्नेंस को सुधारने के लिये भी प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे इनकी कार्यपद्धति में बदलाव लाया जा सके। RBI को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह PSB बैंकों की बैलेंस शीटपर कड़ी नज़र रखे ताकि स्थिति के बिगड़ने से पूर्व ही उसे ठीक किया जा सके। डिजिटलीकरण के दौर में निजी क्षेत्र ने तेज़ी से अपनी कार्यपद्धति में बदलाव किया है तथा नवीन तकनीकों को स्वीकार किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी नवीन तकनीक को उत्साहपूर्वक अपनाना होगा ताकि निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्द्धा की जा सके, साथ ही बैंक सरकार पर बोझ बनने के बजाय सरकार की योजनाओं में सहयोग प्रदान कर सकें। यदि कुछ बैंकों की स्थिति को ठीक करना मुमकिन न हो, तो ऐसे बैंकों के निजीकरण के बजाय उनके विलय पर भी विचार किया जा सकता है, कुछ समय पूर्व सरकार द्वारा कुछ बैंकों का विलय भी किया गया है। बैंकों के विलय से न सिर्फ बैंकों के कार्यकरण में सुधार होगा बल्कि इनके आकार में भी वृद्धि हो सकेगी जिससे ये विश्व के बड़े बैंकों में शामिल हो सकेंगे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत आधार दे सकेंगे।